

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016

विषय : रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना से प्रभावित/विस्थापित परिवारों के लिए पुर्नवास नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1231/पी0एम0यू0/2016-17 दिनांक 23-8-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में जनपद देहरादून स्थित बिंदाल एवं रिस्पना नदियों के सुनियोजित विकास के लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत बिंदाल एवं रिस्पना नदियों की साफ सफाई एवं बाढ़ सुरक्षा तथा नदी के कटाव को रोकने हेतु प्रारम्भिक रूप में नदी की भूमि की उपलब्धता एवं नदियों के प्राकृतिक जल प्रभाव के अनुरूप ही नदियों में रीवर चैनलाईजेशन एवं रिटेनिंग वाल (Retaining Wall) का निर्माण करते हुए नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

2- उक्त कार्यवाही से बिंदाल एवं रिस्पना नदियों के दोनों ओर नदी के किनारे से 50-50 मी0 तक निर्मित भवनों, दुकानों एवं अन्य सम्पत्तियों के प्रभावित होने की सम्भावना है।

3- रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना से प्रभावित होने वाले अध्यासी स्वामी, जिनका अपने अध्यासनरत् भवन का स्वामित्व (स्वामित्व से अभिप्राय भूमिधरी, वैध पट्टेदार, शासन द्वारा आबंटी आदि से है) उनके नाम दर्ज हो, के अध्यासन वाली सम्पत्ति के प्रभावित होने की दशा में निम्नानुसार पुर्नवास/विस्थापन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है -

- (1) आर0एफ0डी0 योजना से प्रभावित भूमि के बदले लैण्ड पूलिंग योजना के तहत भूमि का नकद प्रतिकर अथवा भूमि संयोजन के अनुरूप भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।
- (2) आवासीय भवनों के प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित भवन की निर्माण लागत का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0-332/10 अधिप्राप्ति/10 दिनांक 03-7-2010 एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत दर अनुसूची एवं इस पर समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के अनुसार भवन की प्रकृति को देखते हुए गणना की जायेगी, जिसके पश्चात नकद भुगतान किया जायेगा।

अथवा

- (3) प्रभावित व्यक्ति/परिवार को प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में एम0आई0जी0 अथवा एच0आई0जी0 आवासीय इकाई के आबंटन चाहने पर लाटरी के माध्यम से आवास आबंटन किया जायेगा। आवास आबंटन में प्रभावित के भूमि एवं भवन के मूल्यांकित धनराशि का समायोजन किया जायेगा एवं अतिरिक्त मूल्यांतर का भुगतान एक दूसरे के पक्ष में जमा किया जायेगा।

- (4) यदि प्रभावित व्यक्ति भवनों की निर्माण लागत नहीं लेता है तो उन्हें आर0एफ0डी0 योजना में निर्मित किए गये निकटतम समतुल्य क्षेत्रफल के भूखण्ड को आबंटित किया जायेगा। अवशेष क्षेत्रफल के अन्तर को लैण्ड पूलिंग योजना के तहत प्रतिकर दिया जायेगा।
- (5) सरकारी भूमि पर निर्मित सभी कच्चे अथवा अर्ध पक्के भवनों में निवासरत परिवारों के प्रभावित होने की दशा में उन्हें ई0डब्लू0एस0 भवन रु0 5.00 लाख में आबंटित किया जाएगा।
- (6) सरकारी भूमि पर निर्मित सभी पक्के भवनों में निवासरत परिवारों के आवासीय भवनों का आर0एफ0डी0 योजना से प्रभावित होने की दशा पर निम्नानुसार पुर्नवास/विस्थापन किया जाएगा -
- (i) 40 वर्गमीटर कारपेट एरिया तक के आवासीय भवन के प्रभावित होने पर 01 ई0डब्लू0एस0 भवन रु0 5.00 लाख में आबंटित किया जाएगा।
 - (ii) 41 से 80 वर्गमीटर कारपेट एरिया तक के आवासीय भवन के प्रभावित होने पर 01 एल0आई0जी0 भवन रु0 10.00 लाख में आबंटित किया जाएगा।
 - (iii) 81 वर्गमीटर से अधिक कारपेट एरिया के आवासीय भवन के प्रभावित होने पर 01 एम0आई0जी0 भवन लॉटरी के माध्यम से आबंटित किया जाएगा। एम0आई0जी0 भवनों के आबंटन मूल्य का निर्धारण सम्बन्धित आवासीय परियोजना में इकाई के मूल्य से भूमि का मूल्य कम करते हुए भवनों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी जारी रासनादेश सं0-4049/9-अ-1-99/16 समिति/ 1998 दिनांक 10-10-1999 के अनुसार आंकलित किया जायेगा।
 - (iv) उपरोक्तानुसार प्रभावित व्यक्ति स्वेच्छानुसार एम0आई0जी0 की पात्रता को परित्याग करते हुए एल0आई0जी0 आवास हेतु आवेदन कर सकता है। भवन की उपलब्ध होने पर प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु प्रभावित व्यक्ति को देय अवशेष धनराशि का आंकलन/भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
 - (v) उपरोक्तानुसार ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 हेतु पात्र व्यक्ति/प्रभावित कमशः एल0आई0जी0 एवं एम0आई0जी0 भवन हेतु आवेदन कर सकता है। भवन की उपलब्धता पर उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी तथा उच्च श्रेणी का भवन प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा देय धनराशि का भुगतान प्राधिकरण को किया जायेगा।
- (7) ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों को अधिकतम 15 वर्षों के लिए मासिक किश्तों पर दिया जाएगा। यदि प्रभावित परिवार भारत सरकार की एच0एफ0ए0/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना से आच्छादित होता है तो तदनुसार प्रभावित के आवेदन पर एच0एफ0ए0/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना से आच्छादित लाभ प्रभावित को प्रदत्त किया जायेगा।
- (8) एम0आई0जी0 भवनों का सम्पूर्ण भुगतान आबंटियों को 05 वर्ष के भीतर करना होगा।
- (9) आबंटित भवनों का Locking Period न्यूनतम 10 वर्ष रहेगा। अर्थात् कोई आवंटी आवंटन की तिथि से 10 वर्ष का आवंटित भवनों/भूखण्ड का विक्रय नहीं करेगा।

- (10) प्रभावित परिवारों को अपने अध्यासन के सम्बन्ध में बिजली बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स रसीद, आधार कार्ड अथवा वोटर कार्ड साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने होंगे।
 - (11) प्रभावितों के चयन/अध्यासन के सम्बन्ध में कट ऑफ डेट शासन की विनियमितीकरण नीति की भांति 31 मार्च, 2016 से पूर्व प्रभावित होने वाले स्थल पर निवासरत परिवारों पर ही लागू होगी।
 - (12) उक्त भवनों का आबंटन एवं निजी भवनों हेतु व्यय प्रतिकर का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
 - (13) प्रभावित व्यक्ति को भवन आबंटन करने के उपरांत ही प्रभावित स्थल से हटाये जाने की कार्यवाही की जाये।
 - (14) आर0एफ0डी0 योजना से प्रभावित के पुर्नवास के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसके निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है जिसमें निम्न सदस्य होंगे -
 - (i) जिलाधिकारी देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो कि अपर जिलाधिकारी के स्तर से निम्न स्तर का न हो।
 - (ii) नगर आयुक्त, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अपर मुख्य नगर अधिकारी के स्तर से निम्न स्तर का न हो।
 - (15) गठित समिति के निर्णय क्षुब्ध व्यक्ति आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील कर सकता है। अपील के निस्तारण से पूर्व आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा।
- 4- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

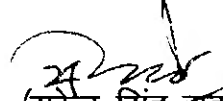
(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या-1434/V-2-2016-25(आ0)/2015 टी0सी0-2 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 2- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 3- नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

आज्ञा से,


(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव